



पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002
दूरभाष नं० 0135-2645249 फैंक्स नं० 0135-2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: /मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4

दिनांक: 24.07.2019

विषय :-समस्त सरकारी कॉलोनियों में कूड़े का स्रोत पर पृथक्कीकरण एवं जैविक कूड़े से विकेंद्रित कम्पोस्टिंग का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1215/1(2)/2019-05(सी०एस०)-01/2012 दिनांक 02.07.2019 एवं उसके साथ संलग्न पत्र संख्या 164/श०वि०/नि०स०/2019 दिनांक 12.06.2019 की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सलग्नक:-यथोपरि।

(ए०के० जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)

पत्रांक: 1053/मा०सं०एवंप्र०अनु०/पिटकुल/जी-4 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सहायक-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (मा०सं०)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (सू०प्रौ०), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त पत्र को संलग्नको सहित पिटकुल की वेबसाइट में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(ए०के० जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा०सं०)

संख्या- / 2 / 8 / 1(2) / 2019-05(सी0एस0)-01 / 2012

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

No. 1822 / MD/PTCULI... Dt. 9.7.19

Dir (HR)

9
(21A)

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उपाकालि / पिटकुल,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 02 जून, 2019

विषय:- समस्त सरकारी कॉलोनियों में कूड़े का स्रोत पर पृथक्कीकरण एवं जैविक कूड़े से विकेंद्रित कम्पोस्टिंग का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-164 / श०वि० / नि०स० / 2019 दिनांक 12.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त सरकारी कॉलोनियों में कूड़े का स्रोत पर पृथक्कीकरण एवं जैविक कूड़े से विकेंद्रित कम्पोस्टिंग का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2. उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)

संयुक्त सचिव।

संख्या- / 1(2) / 2019, 05(सी0एस0)-01 / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को पत्र सं०-164 / श०वि० / नि०स० / 2019 दिनांक 12.06.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

HR/Admin./PTCUL/Dun
Diary No. 1172
File.....
Date 12/7/19

कार्यालय में पत्र प्राप्ति की तिथि 9.7.19

प्राप्तकर्ता
कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

Dir (HR)

11/7/19

SPO
11/7



11/7

2825/sec-E/19

AS(1+2)Emerg

क,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

म. वि. चिन्दा जोशी
प्रमुख निजी सचिव,
सचिव म. मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा
उत्तराखण्ड शासन

दिनांक:- 12 जून 2019

विषय :- समस्त सरकारी कॉलोनीयों में कूड़े का स्रोत पर पृथक्कीकरण एवं जैविक कूड़े से विकेंद्रित कम्पोस्टिंग का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अंतर्गत कूड़े को गीला कूड़ा (जैविक कूड़ा) एवं सूखा कूड़ा (अजैविक कूड़ा) के रूप में स्रोत पर पृथक्कीकरण किया जाना अनिवार्य हैं। उक्त के अतिरिक्त 5000 वर्ग मी0 क्षेत्र में अवस्थित समस्त आवासीय कॉलोनीयों, वाणिज्यिक संस्थानों, होटल व रेस्ट्रा आदि के लिये अनिवार्य है कि कम्पोस्टिंग के माध्यम से जैविक कूड़े का प्रसंकरण, उपचार एवं निस्तारण यथासंभव अपने परिसर में ही सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि प्रतिदिवस उत्पादित घरेलू कूड़े में जैविक कूड़े की मात्रा लगभग 50% होती है।

2. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा गीले कूड़े (जैविक कूड़े) के विकेंद्रित प्रसंकरण पर बल दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बंध में Advisory on On-Site and Decentralized Composting of Municipal Organic Waste भी जारी की गई है, जिसमें विकेंद्रित कम्पोस्टिंग की विभिन्न अल्प लागत युक्त तकनीके सुझायी गई है। उक्त एडवाइजरी की सॉफ्ट प्रति ई-मेल के माध्यम से सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। उल्लेखनीय है कि कतिपय राज्यों द्वारा इस दिशा में अनुकरणीय व सफल उदाहरण भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

3. उत्तराखण्ड राज्य का 86% भूभाग पर्वतीय जबकि 66% भूभाग वनाच्छादित है। भूमि की सीमितता के दृष्टिगत जैविक कूड़े के विकेंद्रित प्रसंकरण की प्रासंगिकता उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैविक कूड़े के विकेंद्रित प्रसंकरण के फलस्वरूप जहाँ भूमि की आवश्यकता में वृहत कमी आ सकेगी वहीं दूसरी ओर कूड़ा संग्रहण एवं परिवहन लागत में भी अपेक्षित कमी संभव हो सकेगी।

4. कूड़े का स्रोत पर पृथक्कीकरण एवं गीले कूड़े (जैविक कूड़े) का विकेंद्रित प्रसंकरण राज्य में अवस्थित समस्त सरकारी कॉलोनीयों में अभिनव प्रयोग के रूप में आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः अनुरोध है कि अपने विभागान्तर्गत आच्छादित समस्त सरकारी कॉलोनीयों में जैविक कूड़े के विकेंद्रित प्रसंकरण को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. सचिव, शहरी विकास विभाग उक्त कार्य हेतु नोडल अधिकारी होंगे। समस्त विभागों से अपेक्षा है कि कृत प्रगति की सूचना मासिक आधार पर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

-J. S. (En.)

AS

2157/AS-(E)
21/6/1912/6/19
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासनUS(T)
19/6/19502
11
20/6/19

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव

श्री सुरेश
21.6.2019

सख्या एवं दिनांक तदैव।

तिलिपि:-

1. मण्डलायुक्त, कूमाऊँ एवं गढवाल को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मण्डल अंतर्गत उक्त महत्वपूर्ण पहल के कियान्वयन का नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करे।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि जनपद अंतर्गत उक्त महत्वपूर्ण पहल का सुचारु कियान्वयन एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करे।
3. गार्ड फाईल।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव